



Yojna IAS

G-32 NOIDA SECTOR-02
UTTAR PRADESH (201301)
CONTACT No. +8595907569

CURRENT AFFAIRS



Date – 10 August 2022

इज़राइल और फिलिस्तीन



- इज़राइल और फ़िलिस्तीन ने हाल ही में तीन दिनों की हिंसा के बाद युद्धविराम समाप्त किया जिसमें दोनों देशों में दर्जनों लोग मारे गए थे।
- इस साल की शुरुआत में, यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों और इज़राइली पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था।
- ये आवर्ती संघर्ष चल रहे इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का हिस्सा हैं।

वर्तमान संघर्ष:

संघर्ष का कारण:

- इजरायली विमानों ने गाजा में (इस्लामिक जिहाद के नेताओं) को निशाना बनाया।
- जवाब में, ईरानी समर्थित फ़िलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इज़राइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे।
- इस्लामिक जिहाद में हमास की तुलना में कम लड़ाके और समर्थक हैं।

इजरायली कार्रवाई:

- इजरायल ने अपने अभियान की शुरुआत एक इस्लामिक जिहाद नेता पर हमले के साथ की और हमले के इरादे से एक अन्य प्रमुख नेता ने पीछा किया।

गाजा कार्रवाई:

- इस्राइली सेना के अनुसार, आतंकवादियों ने गाजा में इजरायल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे।
- इस्राएल ने उनमें से बहुतों को रोका और दो को मार डाला जो यरूशलेम की ओर चलाए गए थे।

यूएनएससी की बैठक:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को लेकर एक आपात बैठक निर्धारित की।
- चीन, जो अगस्त 2022 के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा, ने संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के जवाब में सत्र निर्धारित किया, जो परिषद में अरब देशों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ चीन, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे भी।

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद:

यरूशलेम पर विवाद:

- यरूशलम इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 1947 की मूल विभाजन योजना के अनुसार, जेरूसलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- हालांकि, 1948 के पहले अरब-इजरायल युद्ध में, इजरायल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और प्राचीन शहर, जहां हराम अल-शरीफ स्थित है, सहित पूर्वी हिस्से पर जॉर्डन का कब्जा था।
- 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के बाद, इजराइल और अरब राज्यों के एक गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र, वक्फ के जॉर्डन मंत्रालय शामिल थे, जिसने तब तक अल-अक्सा मस्जिद को नियंत्रित करना बंद कर दिया था।
- 1967 के छह दिवसीय युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया।
- इस्राइल ने विलय के बाद पूर्वी यरूशलम में बस्तियों का विस्तार किया।
- इजराइल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि वह भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि पूर्वी यरूशलम को इसकी राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

हाल की गतिविधि:

अल-अक्सा मस्जिद और शेख जराह:

- मई 2021 में इजरायली सशस्त्र बलों ने ज़ायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजरायल के कब्जे की स्मृति में एक मार्च से पहले यरूशलेम के हराम अल-शरीफ में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला किया।
- पूर्वी यरूशलम में दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की शेख जराह की धमकी ने संकट को और बढ़ा दिया।

वेस्ट बैंक सेटलमेंट:

- इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य अभ्यास के लिए इज़राइल द्वारा चुने गए क्षेत्र में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के ग्रामीण हिस्सों से 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी निवासियों को निकालने के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया है।
- निर्णय ने हेब्रोन के पास एक चट्टानी, शुष्क क्षेत्र में आठ छोटे गांवों को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे फिलिस्तीनियों द्वारा मसाफर यट्टा के रूप में जाना जाता है और दक्षिण हेब्रोन हिल्स इजरायलियों के लिए।

संकट पर भारत का रुख:

- भारत हाल के वर्षों में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संबंध बनाए रखने के लिए एक डी-हाइफ़्रनेशन नीति का पालन कर रहा है।
- दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के प्रति भारत की नीति स्पष्ट रूप से पहले चार दशकों के लिए फिलिस्तीनी समर्थक थी लेकिन इजरायल के साथ तीन दशकों से अधिक के मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण फिलिस्तीन के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।
- 2017 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, भारत के प्रधान मंत्री ने केवल इज़राइल का दौरा किया, न कि फ़िलिस्तीन का।
- प्रधान मंत्री की फ़िलिस्तीन (2018), ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की हालिया यात्रा फिर से इसी तरह की नीति की निरंतरता है।

स्वदीप कुमार

भारत की अक्षय ऊर्जा



- भारत सरकार ने 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

- भारत ने 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने, 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण फोटोवोल्टिक क्षमता हासिल की है, जो 2010 में 10 मेगावाट से कम थी और 2022 में 50 गीगावाट से अधिक थी।
- भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 4 गीगावाट है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल स्थापित क्षमता का विवरण निम्नलिखित है:

- पवन ऊर्जा: 08 गीगावाट
- सौर ऊर्जा: 34 GW
- बायोपावर: 61 गीगावाट
- लघु जल विद्युत: 83 GW
- बड़ा हाइड्रो: 51 GW

वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता:

- भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता वाले 45 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।
- पावागढ़ (2 GW), कुरनूल (1 GW) और भादला-II (648 MW) के सोलर पार्क देश के शीर्ष 5 चालू सोलर पार्कों में से हैं, जिनकी क्षमता 7 GW है।
- गुजरात में 30 गीगावाट सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना का विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है।

चुनौतियां:

आयात पर अत्यधिक निर्भरता :

- भारत के पास पर्याप्त मॉड्यूल और पीवी सेल निर्माण क्षमता नहीं है।
- वर्तमान सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्रति वर्ष 15 GW तक सीमित है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 5 GW के आसपास है।
- इसके अलावा, मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 15 GW में से केवल 3-4 GW मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और ग्रिड-आधारित परियोजनाओं में परिनियोजन के लिए पात्र हैं।

आकार और तकनीक:

- अधिकांश भारतीय उद्योग एम2 प्रकार के वेफर आकार, लगभग 156×156 मिमी² पर आधारित है, जबकि वैश्विक उद्योग पहले से ही एम10 और एम12 आकारों की ओर बढ़ रहा है, जो 182×182 मिमी² और 210×210 मिमी² हैं।
- बड़े आकार का वेफर फायदेमंद है क्योंकि यह लागत प्रभावी है और इसमें कम बिजली की हानि होती है।

कच्चे माल की आपूर्ति:

- सबसे महंगा कच्चा माल सिलिकॉन वेफर भारत में निर्मित नहीं होता है।
- यह वर्तमान में 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% कोशिकाओं का आयात करता है।
- इसके अलावा, अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे चांदी और एल्यूमीनियम धातु के पेस्ट का लगभग 100% विद्युत संपर्क स्थापित करने के लिए आयात किया जाता है।

सरकार की पहल:

विनिर्माण को समर्थन देने के लिए पीएलआई योजना:

- इस योजना में ऐसे सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करके उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना का समर्थन करने के प्रावधान हैं।

घरेलू सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर):

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कुछ मौजूदा योजनाओं में सरकारी सब्सिडी के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण- II, पीएम-कुसुम और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण- II शामिल हैं। सौर पीवी सेल और मॉड्यूल घरेलू स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा, सरकार ने ग्रिड से जुड़ी राज्य/केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) से ही मॉड्यूल खरीदना अनिवार्य कर दिया है।

सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क का अधिरोपण:

- सरकार ने सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) लगाने की घोषणा की है।
- इसके अलावा, इसने मॉड्यूल के आयात पर 40% और सेल के आयात पर 25% का शुल्क लगाया है।
- मूल सीमा शुल्क एक निर्दिष्ट दर पर वस्तु के मूल्य पर लगाया जाने वाला शुल्क है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक योजना है।
- यह योजना मुख्य रूप से पीवी सेल और मॉड्यूल पर पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है – विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%।

YOJNA IAS

स्वदीप कुमार

**एन. कलैसेल्वी, CSIR की पहली
महिला प्रमुख**

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला महानिदेशक की नियुक्ति की है।

- एन. कलैसेल्वी, वर्तमान में सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CECRI), कराईकुडी, तमिलनाडु के निदेशक, अब 38 प्रयोगशालाओं और लगभग 4,500 वैज्ञानिकों के नेटवर्क का नेतृत्व करेंगे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से एक नोट के अनुसार उन्हें दो साल के लिए नियुक्त किया गया है।
- डॉ. कलैसेल्वी का शोध कार्य 25 वर्षों से अधिक का है और यह विद्युत रासायनिक शक्ति प्रणालियों और इलेक्ट्रोड सामग्री के विकास, कस्टम-डिज़ाइन संश्लेषण विधियों, प्रतिक्रिया मापदंडों को अनुकूलित करने और ऊर्जा भंडारण उपकरणों को बनाने के लिए घर में तैयार इलेक्ट्रोड सामग्री के विद्युत रासायनिक मूल्यांकन पर केंद्रित है। उनके शोध के हितों में लिथियम और लिथियम बैटरी से परे, सुपरकेपसिटर और ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रो-कैटेलिटिक अनुप्रयोगों के लिए अपशिष्ट से धन संचालित इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल हैं।
- तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अंबासमुद्रम गांव से CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में प्रमुख होने तक, डॉ. कलैसेल्वी के लिए यह एक लंबी यात्रा रही है। अपने पैतृक जिले में तमिल माध्यम के स्कूल में पढ़ने के बाद, उन्होंने चिदंबरम में अन्नामलाई विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी।
- फरवरी 2019 में, डॉ. कलैसेल्वी को कराईकुडी स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CECRI) का निदेशक नियुक्त किया गया था। यह पहली बार है जब CECRI के किसी वैज्ञानिक को CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
- डॉ. कलैसेल्वी को शिक्षाविदों के बीच "लिथियम बैटरी विशेषज्ञ" के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कई शोध पत्र लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके क्रेडिट में छह पेटेंट हैं और वह पीएचडी डिग्री हासिल करने में शोधार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक थीं।



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR):

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 1942 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसके महानिदेशक शेखर सी। मंडे हैं जिन्होंने 2018 में कार्यभार संभाला।
- अपनी स्थापना के बाद से, सीएसआईआर पूरे देश में 38 प्रयोगशालाओं/संस्थानों, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार केंद्रों और 5 इकाइयों के साथ भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन बन गया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का इतिहास

- 1930 के दशक में भारत में प्राकृतिक संसाधनों और नए उद्योगों के विकास के लिए अनुसंधान संगठनों की स्थापना की आवश्यकता बढ़ रही थी। प्रमुख वैज्ञानिक जैसे सी.वी. रमन (21 नवंबर, 1970 को पारित) और जे.सी. घोष ने वैज्ञानिक अनुसंधान के एक सलाहकार बोर्ड का प्रस्ताव रखा।

- कलकत्ता और बंगलौर में भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रमशः एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और एक भारतीय विज्ञान अकादमी शुरू करने की योजनाएँ शुरू कीं।
- 1933 में पांचवें उद्योग सम्मेलन में, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और उड़ीसा की प्रांतीय सरकारों ने सर्वसम्मति से औद्योगिक अनुसंधान के लिए एक समन्वय मंच की अपनी मांग दोहराई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने प्राकृतिक संसाधनों के लिए अनुसंधान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना अनावश्यक पाया। इसके बजाय, उन्होंने एक औद्योगिक खुफिया और अनुसंधान ब्यूरो बनाने की पेशकश की, जो अप्रैल 1935 में लागू हुआ।
- 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, तो ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए धन को हटाने का फैसला किया। यह तब था जब आरकोट रामास्वामी मुदलियार ने सिफारिश की थी कि ब्यूरो को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड के लिए जगह बनाने के लिए। चूंकि वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, इसलिए उनकी सिफारिश पर असर पड़ा। 1 अप्रैल 1940 को बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (BSIR) बनने पर उनकी सिफारिश का भुगतान किया गया। मुदलियार को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया।
- अपनी स्थापना के बाद से, BSIR की उपलब्धियों में ईंधन के रूप में वनस्पति तेल मिश्रणों पर अनुसंधान का विकास, सेना के जूते और गोला-बारूद के लिए प्लास्टिक पैकिंग केस, वर्दी के लिए रंग और विटामिन की तैयारी शामिल है।
- तब मुदलियार और भटनागर के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का गठन किया गया था। इस प्रकार, सीएसआईआर 26 सितंबर 1942 को परिचालन में आया जब औद्योगिक अनुसंधान में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया।

सीएसआईआर के उद्देश्य और मिशन

- यह 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 5 इकाइयों के गतिशील नेटवर्क के साथ एक अखिल भारतीय संगठन है। सीएसआईआर देश भर में 8000 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है और विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था।
- **नीचे चर्चा की गई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के मुख्य उद्देश्य हैं:**
- रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, दवाएं, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और खनन, वैमानिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नैनो प्रौद्योगिकी विभिन्न स्पेक्ट्रम हैं जो सीएसआईआर के अंतर्गत आते हैं
 - इसका उद्देश्य सामाजिक प्रयासों के संबंध में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना है
 - सीएसआईआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
- संगठन ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वांछित तंत्र का संचालन किया है, जो आगे चलकर नए आर्थिक क्षेत्रों के विकास को रेखांकित करते हुए नवाचारों के सृजन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगा।

- सीएसआईआर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसरों के परिदृश्य को बदलने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अंततः CSIR को इस ओर प्रेरित किया है: विज्ञान और इंजीनियरिंग नेतृत्व
 - अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान
 - ट्रांसडिसिप्लिनरी क्षेत्रों में प्रतिभा का पोषण
 - विज्ञान आधारित उद्यमिता

सीएसआईआर की संरचना

- दी गई छवि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की संगठनात्मक संरचना को दर्शाती है। उम्मीदवार छवि का उल्लेख कर सकते हैं और संगठन के कामकाज के बारे में जान सकते हैं:



उल्लेखनीय उपलब्धियां:

- स्वदेशी रूप से विकसित सिंथेटिक दवा, मेथाक्वालोन का विकास
- 1967 में भारत के पहले ट्रेक्टर – स्वराज – का डिजाइन
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों की आनुवंशिक विविधता का विश्लेषण करने वाला भारत का पहला संगठन।
- भारत का पहला समानांतर प्रोसेसिंग कंप्यूटर, फ्लोसोल्वर डिज़ाइन किया गया।
- डिगबोई में आधुनिक आसवन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरियों में से एक का उन्नयन

- 'पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी' की स्थापना, जिसे पांच भाषाओं – अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में एक्सेस किया जा सकता है।
- घाव भरने के लिए हल्दी (हल्दी) और नीम को कीटनाशक के रूप में उपयोग करने के लिए अमेरिका में पेटेंट के अनुदान को सफलतापूर्वक चुनौती दी।
- 2009 में मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया
- 2020 में, COVID-19 रोगियों में मृत्यु दर को कम करने के लिए सेप्सिवैक की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया।

रवि सिंह

